

[2016] 1 एससीआर 151

एम /एस. साइमेड ओवरसीज आई एन सी

बनाम

बीओसी इंडिया लिमिटेड और अन्य।

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सी) संख्या 2008 की
संख्या 29125)

जनवरी 11, 2016

[मदन बी. लोकर और आर. के. अग्रवाल, जे.जे.]

लागत - अधिरोपण - मिथ्या या भ्रामक शपथपत्र दाखिल करने के लिए - _ कार्य संविदा के अवार्ड को चुनौती देने वाली रिट याचिका - इसकी अनुरक्षणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया - उच्चतम न्यायालय में अपील में, ठेकेदार ने शपथ पत्र दायर किया कि कार्य पूरा होने वाला था -

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने का निदेश दिया - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने शपथ पत्र के मद्देनजर, ठेका दिए जाने को रद्द नहीं किया और ठेका दिए जाने को चुनौती देने वाले पक्ष को क्षतिपूत के लिए वाद दायर करने की स्वतंत्रता दी - ठेकेदार द्वारा अंतर-न्यायालय अपील में, सत्यापन पर खंडपीठ ने पाया कि शपथ पत्र पर दिया गया बयान गलत था - ठेकेदार ने शुरू में अपने हलफनामे को सही ठहराया और फिर बिना शर्त माफी दायर की गई - डिवीजन बेंच ने माफी को खारिज करते हुए कहा कि ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा दायर किया था और ठेकेदार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था

- अपील पर, यह कहा गया मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि हलफनामा प्रामाणिक था और अदालत को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया था - यह तथ्य कि एक गलत या भ्रामक बयान दिया गया था, अपने आप में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है - लागत का अधिरोपण, हालांकि कुछ हद तक स्वीप था, पूरी तरह से उचित था - शपथपत्र।

शपथ पत्र - न्यायालयों के समक्ष झूठे हलफनामे दाखिल करना - आयोजित: झूठे हलफनामे दाखिल करने और उसी में खतरनाक वृद्धि हुई है दृढ़ता से हतोत्साहित करने की जरूरत है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट

अभिनिर्धारित : 1. यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय में दायर आफतिदावित में दिया गया बयान गलत बयान नहीं था, बल्कि वास्तविक था और इस न्यायालय को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था। ठेकेदार द्वारा दिए गए बयान की सत्यता की न केवल एकल न्यायाधीश द्वारा बल्कि खंडपीठ द्वारा भी बारीकी से जांच की गई और यह पाया गया कि इसके द्वारा अभी भी काफी मात्रा में काम पूरा किया जाना बाकी था और ऐसा नहीं था कि कार्य पूरा होने वाला था जैसा कि इस न्यायालय को दर्शाया गया था।

इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से दी गई रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि ठेकेदार द्वारा अभी भी काफी मात्रा

में काम किया जाना बाकी है। उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद, ठेकेदार ने भी महसूस किया कि उसने वास्तव में इस न्यायालय को गुमराह किया है। फिर भी, ठेकेदार ने झूठे या भ्रामक हलफनामे को सही ठहराने की कोशिश की। औचित्य देने के बाद, इसने बिना शर्त और अयोग्य याचिका दायर की। बिना शर्त और बिना शर्त माफी की कोई आवश्यकता नहीं थी जब तक कि यह स्वीकार नहीं किया गया था कि इस न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान झूठा या भ्रामक था। [पारस [157-एफ-जी, एच; 158-ए; 159-बी]]

यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कथित रूप से झूठे या भ्रामक बयान का इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ठेकेदार को उच्च न्यायालय को सूचित किए बिना रिट याचिका (प्रतिवादी-कंपनी द्वारा मूल्य बोली खोलने के लिए डी ठेकेदार को निमंत्रण को चुनौती देते हुए) के लंबित रहने के दौरान कार्य आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य आदेश के माध्यम से जाता है, इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर एक गलत या भ्रामक बयान दिया गया था। इस मामले का तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष एक गलत या भ्रामक बयान दिया गया था, और यह अपने आप में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। [अनुच्छेद 23 और 29] [157-जी; 159-ई,

आर. करुप्पन, एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्यवाही 2001 (3) एससीआर 750 = 2001 (5) सिका 289; मुथु करुप्पन वि. 2011 (5) एससीआर 329 = 2011 (5) एससीसी 496 - पर भरोसा किया।

2. झूठे हलफनामे को दाखिल करने से संबंधित मामलों की वैश्विक खोज से पता चलता है कि रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या ने पिछले पंद्रह वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या की तुलना में खतरनाक वृद्धि दर्शाई है। यह 'प्रवृत्ति' निश्चित रूप से एक अस्वास्थ्यकर है जिसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि झूठे हलफनामे दाखिल करने को एक नियमित और सामान्य मामला माना जाए। [पैरा 2] [153-एफ-जीजे

3. इस न्यायालय के समक्ष सामग्री और उच्च न्यायालय द्वारा विचार की गई सामग्री के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा लागत लगाना उचित था। लागत लगाना, हालांकि कुछ हद तक खड़ी थी, पूरी तरह से उचित था। उच्च न्यायालय द्वारा ।

यह भी माना गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुबंध अनुचित तरीके से दिया गया था और एक वाणिज्यिक प्रकृति का था, अंतिम दो निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई थी।

[अनुच्छेद 1 और 32] [153-ई; 160-एच]

केस लेट संदर्भ

2001 (3) एससीआर 750

पैरा 30

2011 (5) एससीआर 329

पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की विशेष अनुमति

याचिका (सी) संख्या 29125

उच्च न्यायालय के दिनांक 22.09.2008 के निर्णय और
आदेश से

2008 के एलपीए नंबर 212 में रांची में झारखंड की।

ए। के। गांगुली, देवाशीष भारुका, रवि भारुका फोर थे

गोपाल प्रसाद, के. एल. मेहता एंड कंपनी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

मदन बी. लोकुर, जे. 1. हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने इस अदालत में झूठा या भ्रामक हलफनामा दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने में सही था। हमारी राय में, लागत लगाना, हालांकि कुछ हद तक अधिक थी, पूरी तरह से उचित थी क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुबंध अनुचित तरीके से दिया गया था और एक वाणिज्यिक प्रकृति का था, पिछले दो निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई थी।

2. झूठे हलफनामे को दाखिल करने से संबंधित मामलों की वैश्विक खोज से पता चलता है कि रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या ने पिछले पंद्रह वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या की तुलना में खतरनाक वृद्धि दर्शाई है। यह उस अस्वस्थता का उदाहरण है जो धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से रेंग रही है। यह 'प्रवृत्ति' निश्चित रूप से एक अस्वास्थ्यकर है जिसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि झूठे हलफनामे दाखिल करने को एक नियमित और सामान्य मामला माना जाए।

3. याचिकाकर्ता झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2008 के एलपीए संख्या 212 में पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 22 सितंबर, 2008 से केवल लागत लगाने की सीमा तक व्यथित है।^स हमारी राय में, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

4. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (संक्षेप में रिम्स के लिए) ने 10 फरवरी, 2007 को निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया। निविदा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और संपीड़ित हवा आदि के लिए मेडिकल गैस पाइप लाइन के साथ केंद्रीकृत तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की एक पूरी प्रणाली की स्थापना और आपूर्ति के लिए थी। रिम्स के 1000 बिस्तरों वाले विभागों और वार्डों में 150 दिनों के भीतर टर्नकी आधार पर कार्य किया जाना था।
5. निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के उत्तर याचिकाकर्ता (साइमेड ओवरसीज) और प्रतिवादी सं 1 (बी ओ सी इंडिया) द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उनकी निविदाओं पर आरआईएमएस द्वारा कार्रवाई की गई थी और इसके निदेशक द्वारा 25 जून, 2007 को एक ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें साइमेड और बीओसी को सूचित किया गया था वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की मूल्य बोली खोलने के संबंध में।
6. बीओसी के अनुसार, तकनीकी बोली की शर्तें साइमेड द्वारा पूरी नहीं की गई थीं और इसलिए मूल्य बोली खोलने के लिए इसे आमंत्रित करने का कोई कारण नहीं था। बीओसी द्वारा रिम्स को इस संबंध में एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया और इसलिए, बीओसी ने साइमेड और रिम्स के खिलाफ अपनी शिकायत के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में 2007 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4203 दायर की।
7. उच्च न्यायालय ने बीओसी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार किया और दिनांक 31 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा रिम्स को दिए गए अपने पूर्व अभ्यावेदन के क्रम में बीओसी को दूसरा अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका का निपटान कर दिया गया। यह निर्देश दिया गया था कि दोनों अभ्यावेदनों पर रिम्स के निदेशक द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उन पर एक उचित तर्कसंगत आदेश पारित किया जाना चाहिए।

8. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब 3 जुलाई, 2007 को उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा किया गया था, तो रिम्स या साइमेड द्वारा उच्च न्यायालय को इस आशय की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि लगभग एक सप्ताह पहले, यानी 25 जुलाई, 2007 को निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के संबंध में साइंस को पहले ही एक कार्य आदेश जारी किया जा चुका था।

9. यह तथ्य पहली बार बीओसी के ध्यान में लाया गया था जब रिम्स के जी निदेशक ने दिनांक 8 सितंबर, 2007 के अपने पत्र में बीओसी को अभ्यावेदनों के जवाब में सूचित किया था कि 25 जुलाई 2007 को साइमेड को कार्य आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था।

10. इन परिस्थितियों में, बीओसी ने 2007 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4830 की एक और याचिका को प्राथमिकता दी, जिसमें साइमेड के पक्ष में एच वर्क ऑर्डर जारी करने को चुनौती दी गई थी

11. 10 सितम्बर, 2007 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बीओसी द्वारा दायर दूसरी रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रश्न कि क्या साइमेड को कार्य आदेश जारी किया गया था या नहीं, तथ्य का प्रश्न था। इसके अलावा, बीओसी ने तथ्य के कई अन्य प्रश्न भी उठाए थे। उच्च न्यायालय की राय थी कि चूंकि तथ्यात्मक विवादों को उसके रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं था और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया था।

12. खण्ड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हुए बीओसी ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एक याचिका दायर की जिसमें 14 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की गई। इस न्यायालय ने उसी दिन 2008 की सिविल अपील संख्या 2028 होने के नाते अपील का निपटारा कर दिया और कहा कि तथ्य का शायद ही कोई विवादित प्रश्न है। इसके विपरीत, मामले के तथ्य पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों से स्पष्ट थे और मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता थी।

तदनुसार, इस न्यायालय का विचार था कि मामले को उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए और इस संबंध में उचित निर्देश दिया गया था।

13. सिविल अपील के लंबित रहने के दौरान, 20 फरवरी, 2008 को साइमेड द्वारा अपने मालिक शैलेंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया था: -

"यह प्रस्तुत किया गया है कि एनआईटी को आराम दिए जाने और तकनीकी और वित्तीय बोलियों को खोलने के बाद, प्रतिवादी नंबर 5 को याचिकाकर्ता की तुलना में 1.12 करोड़ रुपये के अंतर से सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया था और कार्य आदेश पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और परियोजना लगभग पूरी होने के करीब है और 85% राशि पहले ही जवाब देने वाले प्रतिवादी को जारी की जा चुकी है। वर्तमान एसएलपी को किसी भी मामले में, निष्फल और खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

14. हलफनामे में यह वह अंश है जिसने हमारे सामने विवाद को जन्म दिया है।

15. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, बीओसी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ए द्वारा विचार के लिए लिया गया था। दिनांक 14 मई, 2008 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। रिट याचिका का निपटारा करते समय, यह माना गया था कि हालांकि निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसके द्वारा साइमेड को योग्य घोषित किया गया था, अनुचित था, यह नहीं माना जा सकता था कि आरएलएमएस ने मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण तरीके से

काम किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि साइमेड ने इस न्यायालय के समक्ष कहा था कि काम लगभग पूरा हो गया था। उच्च न्यायालय ने देखा कि चूंकि साइमेड को दिए गए कार्य में काफी हद तक प्रगति हुई थी और धन का एक बड़ा हिस्सा उन्नत किया गया था या साइमेड को भुगतान किया गया था, इसलिए यदि कार्य आदेश को अलग रखा जाना था, तो इसमें उस प्रणाली को खत्म करना और उखाड़ना शामिल होगा जो अब तक तय की गई थी जो सी रोगियों या राजकोष के हित में नहीं होगी। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने साइमेड को अनुबंध के पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन साइमेड के खिलाफ नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने के लिए बीओसी को खुला छोड़ दिया।

16. व्यथित महसूस करते हुए, साइमेड ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक लेटर्स पेटेंट अपील डी को प्राथमिकता दी, जिसे 22 सितंबर, 2008 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने नोट किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने साइमेड को अनुबंध के पुरस्कार में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, इसका कारण इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर दिए गए बयान के कारण था कि काम लगभग पूरा होने वाला था। यह भी नोट किया गया कि उनके स्तर पर ठेका दिए जाने को रद्द करने से सरकार पर भारी प्रशासनिक और वित्तीय बोझ पड़ेगा और करोड़ों रुपये के व्यय में वृद्धि और दोगुना होगा।

17. हालांकि, उच्च न्यायालय ने बीओसी के विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण पर यह सत्यापित करने का निर्णय लिया कि क्या निविदा की सूचना के अनुसार पूरी प्रणाली की स्थापना और आपूर्ति पूरी होने वाली थी, जैसा कि साइमेड ने इस न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा था। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय ने उस न्यायालय के एक सम्मानित अधिवक्ता को कार्य स्थल का दौरा करने और कार्य की सीमा या पूरा होने के चरण के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया।

18. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त विद्वान अधिवक्ता ने 3 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में यह कहा गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, कि अपेक्षित विनिर्देश के मुख्य तरल ऑक्सीजन गैस टैंक का प्रारंभिक बिंदु/इनलेट अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि परियोजना को चालू करने के लिए एक अलग 3-फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। इन दो प्रमुख कमियों को देखते हुए पूरी प्रणाली को चालू करने में विलंब हो रहा था। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया था कि ऑक्सीजन गैस टैंक उस समय बेंगलोर से पारगमन में था।

19. रिपोर्ट पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि साइमेड ने इस न्यायालय में इस आशय का एक झूठा हलफनामा दिया था कि काम पूरा होने वाला था। मामले के इस आलोक में हाईकोर्ट ने साइमेड द्वारा दायर अपील को खारिज

कर दिया और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

20. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि साइमेड ने अपने प्रोपराइटर शैलेंद्र प्रसाद सिंह पुत्र रामेश्वर प्रसाद सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय में 10 जुलाई, 2008 को या उसके बारे में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें यह बताया गया था कि इस न्यायालय में हलफनामे पर दिया गया बयान इसलिए था क्योंकि प्रतिवादी का विचार था कि गैस पाइपलाइन की पूरी प्रणाली की स्थापना पुरस्कार का एक हिस्सा है और तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना एक अलग काम है। यह कहा गया था कि इस न्यायालय में दायर हलफनामा कुछ गलत धारणा के कारण था और इस न्यायालय को गुमराह करने की दृष्टि से नहीं था।

दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी ने विद्वान अधिवक्ता की रिपोर्ट के बावजूद इस न्यायालय में अपने हलफनामे को सही ठहराने की मांग की। उपरोक्त स्पष्टीकरण देने के बाद, प्रतिवादी ने परियोजना के निकट पूरा होने के बारे में बयान के लिए उच्च न्यायालय को बिना शर्त और बिना शर्त माफी मांगी।

उच्च न्यायालय ने साइमेड के मालिक द्वारा दी गई माफी को स्वीकार नहीं किया और इसलिए साइमेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

21. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, साइमेड के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वास्तव में इस न्यायालय में दायर हलफनामे में दिया गया बयान गलत बयान नहीं था, बल्कि यह वास्तविक था और इस न्यायालय को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित रूप से झूठे या भ्रामक बयान का इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

24.हम विद्वान वकील द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

25.साइमेड द्वारा दिए गए बयान की सत्यता की न केवल विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बल्कि डिवीजन बेंच द्वारा भी बारीकी से जांच की गई थी और यह पाया गया था कि साइमेड द्वारा अभी भी काफी मात्रा में काम पूरा किया जाना बाकी था और ऐसा नहीं था कि काम पूरा होने वाला था जैसा कि इस न्यायालय को दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से दी गई रिपोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि साइमेड द्वारा अभी भी काफी मात्रा में काम किया जाना बाकी है। रिपोर्ट एकपक्षीय नहीं थी, बल्कि साइट के निरीक्षण के बाद और साइमेड के मालिक शैलेंद्र प्रसाद सिंह और साइमेड के एक इंजीनियर के साथ-साथ रिम्स के अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी।

26.मुद्दों के गहन निरीक्षण और चर्चा के बाद विद्वान अधिवक्ता द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार है।

"निविदा शर्तों के तहत स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक संपूर्ण तरल ऑक्सीजन गैस प्रणाली के विस्तृत निरीक्षण से, मैं यह पता लगाने में सक्षम था कि आवश्यक विनिर्देश के मूल

बिंदु/इनलेट पर आवश्यक विनिर्देश का मुख्य तरल ऑक्सीजन गैस टैंक अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। मैंने यह भी पाया कि एक अलग डी

परियोजना को चालू करने के लिए 3-फेज विद्युत आपूर्ति प्रणाली अभी तक संस्थापित नहीं की गई है और कथित तौर पर यह प्रक्रियाधीन है। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि 3-फेज बिजली कनेक्शन अस्पताल के अधिकारियों द्वारा आपूर्ति की जानी है और ठेकेदार यानी मैसर्स साइमेट ओवरसीज इंक की ओर से निविदा शर्तों या कार्य आदेश के तहत आवश्यक नहीं है। ठेकेदार यानी प्रतिवादी नंबर 5 1 की ओर से बार-बार सूचित किया गया था कि काम के निष्पादन में देरी मुख्य रूप से महंगे तांबे के पाइपों की बार-बार चोरी, रिम्स में चल रही सफेदी और डिस्टेंपर के काम के कारण हुई है और साथ ही स्त्री रोग विभाग में आईसीयू, ओटी, लेबर रूम में स्थापना में परिचालन और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण है, जिन्हें अस्पताल के अधिकारियों द्वारा बहुत अनुनय के बाद पूरी तरह से खाली करना पड़ा, इससे पहले कि कोई स्थापना की जा सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य तरल ऑक्सीजन टैंक और 3 फेज विद्युत कनेक्शन की स्थापना में विलंब के कारण, अन्य गैसों के साथ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस की पूरी प्रणाली को चालू किया जा रहा है। वैक्यूम और एयर में देरी हो रही है। जैसा कि ऊपर पहले ही कहा जा चुका है, अलग-अलग आउटलेट तक संपूर्ण आउटलेट प्रणाली लागू कर दी गई है। मैंने यह भी देखा कि बेड हेड्स पर शाखा पाइपलाइन के अंत

में अंतिम आउटलेट के बिंदु पर जहां भी उन्हें वर्क ऑर्डर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, पार्किंग सुविधा के साथ डबल लॉकआउट स्थापित किया गया है, लेकिन पैनल में जिन बिजली के स्विच के लिए जगह छोड़ी गई है, उन्हें अभी तक तय नहीं किया गया है।

27.माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन दाखिल होने के बाद साइमेड भी महसूस किया कि उसने कोर्ट को अन्धकार में डाला तथापि साइमेड बिना शर्त अपने प्रोप्राइटर शलेन्द्र प्रसाद सिंह के

द्वारा माफी मांगी साइमेड के प्रोपराइटर शैलेंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से माफी। मालिक को बिना शर्त और बिना शर्त माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब तक कि यह स्वीकार नहीं किया गया था कि इस न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान झूठा या भ्रामक था। यह एक अलग मामला होता अगर साइमेड ने बिना किसी औचित्य के बिना शर्त और बिना शर्त माफी मांगी होती।

28. जहां तक विद्वान वकील के वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण का संबंध है, हम इस निवेदन को भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, खासकर यदि पूरे मामले को व्यापक रूप से देखा जाए।

29. पहली बार में, 25 जुलाई, 2007 को साइमेड को कार्य आदेश जारी किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय को इसका खुलासा नहीं किया गया था जब उसने 31 जुलाई, 2007 को 2007 की रिट याचिका (सी) संख्या 4203 का निपटारा किया था । अगर उच्च न्यायालय में तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा किया गया होता, तो शायद बीओसी द्वारा दायर रिट याचिका का परिणाम अलग होता और यह मुद्दा इस न्यायालय तक भी नहीं जाता। इसके अलावा, स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य आदेश पारित हो जाए, इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर एक गलत या भ्रामक बयान दिया गया था जब 14 मार्च, 2008 को इस मामले को लिया गया

था कि काम पूरा होने वाला था। विद्वान वकील द्वारा दिए गए विचार को स्वीकार करना संभव नहीं है कि झूठे या भ्रामक बयान का 14 मार्च, 2008 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम इस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में क्या हुआ और न ही हम कल्पना कर सकते हैं कि 14 मार्च, 2008 को अपना निर्णय देते समय इस न्यायालय के साथ क्या महत्व हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था। इस मामले का तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष एक गलत या भ्रामक बयान दिया गया था और यह अपने आप में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद, साइमेड ने यह भी महसूस किया कि इसने वास्तव में इस न्यायालय को गुमराह किया था। फिर भी, साइमेड ने इस अदालत में दायर झूठे या भ्रामक हलफनामे को सही ठहराने की कोशिश की। औचित्य देने के बाद, साइमेड ने बिना शर्त और अयोग्य निविदा दी

30. आर. करुप्पन एडवोकेट के खिलाफ स्वतः संज्ञान कार्यवाही के मामले में,

इस न्यायालय ने कहा था कि पक्षकारों द्वारा दायर हलफनामों की पवित्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए और साथ ही सटीकता की परवाह किए बिना गैर-जिम्मेदार बयान दर्ज करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए

इस न्यायालय द्वारा यह निम्नानुसार देखा गया था:

"अदालतों को समाज के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अपराधियों की आपराधिक देयता का निर्धारण करने के अलावा पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों के न्याय के वितरण और न्याय के निर्णय की शक्तियां सौंपी गई हैं। न्यायालयों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी बाहरी विचार से पक्षपातपूर्ण न होकर शीघ्र और निष्पक्ष रूप से न्याय करें। यदि उन वादियों पर वैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, जो विशेष रूप से उन मामलों में झूठे साक्ष्य दाखिल करके और उन पर भरोसा करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो न्याय वितरण प्रणाली बर्बाद हो जाएगी, जिसका निर्णय तथ्यों के बयान पर निर्भर है। यदि कार्यवाही के परिणाम का सम्मान किया जाना है, तो न्यायालय के समक्ष इन मुद्दों को सत्यता के अनुसार

यथासंभव हल किया जाना चाहिए। अदालत की कार्यवाही की पवित्रता को किसी पक्ष द्वारा तुच्छ, कष्टप्रद या अपर्याप्त आधार पर या बाहरी विचारों से प्रेरित झूठे सबूतों पर भरोसा करने या अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने या उसके बावजूद

प्रतिशोधी इच्छा पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सटीकता की परवाह किए बिना, गैर-जिम्मेदाराना बयान दाखिल करने को हतोत्साहित करने के लिए हलफनामों की पवित्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए।

31. इसी तरह, मुथु करुप्पन बनाम परिथी लमवाझुथी में ¹ इस ई कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि झूठे हलफनामे को प्रभावी ढंग से मजबूत हाथ से रोका जाना चाहिए। यह सच है कि अवलोकन न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के संदर्भ में किया गया था, लेकिन न्यायिक कार्यवाही की शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्यक्त किए गए विचार को आम तौर पर समर्थन दिया जाना चाहिए। यह वही है जो कहा गया था:

"झूठा हलफनामा दायर करके झूठे साक्ष्य देना एक बुराई है जिसे प्रभावी ढंग से मजबूत हाथ से रोका जाना चाहिए। अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब अपराधी को दंडित करने के लिए न्याय के हित में समीचीन माना जाता है, लेकिन पदार्थ के मामले पर "जानबूझकर झूठ" का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए एक उचित आधार है।

32. हमारे समक्ष सामग्री और उच्च न्यायालय द्वारा विचार की गई सामग्री पर, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा

¹ (201 1) 5 एससीसी 496

लागत लगाना उचित था। हमें विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है

[मदन बी. लोकर, जे.]

याचिका खारिज की जाती है।

33. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण (झालसा) के साथ उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित लागत जमा करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं। जमा किए जाने पर, झालसा को राशि बीओसी इंडिया को अग्रेषित करनी चाहिए। मामले को अनुपालन के लिए आठ सप्ताह के बाद उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

कल्पना के. त्रिपाठी

एसएलपी बर्खास्त।

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।